



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2010/आषाढ़ 1, 1932

No. 172]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2010/ASADHA 1, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

(निर्णायक समीक्षा)

विषय :—चीन जन. गण. के मूल से अथवा वहां से निर्यातित सोडियम फॉर्मेलिडहाइड सल्फोजाइलेट (एसएफएस) पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

सं. 15/16-2009-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा जाएगा) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का अभिज्ञान आकलन, तथा वसूली तथा क्षति निर्धारण हेतु) नियम, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् पाटनरोधी नियम कहा जाएगा), को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा जाएगा) में 26 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. 14/25/2004-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम फॉर्मेलिडहाइड सल्फोजाइलेट (एसएफएस) जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी ने 25 जनवरी, 2006 की अधिसूचना सं. 14/25/2004-डीजीएडी द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी किया था। जांच परिणाम के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 11 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. 95/2000 सीमा-शुल्क तथा दिनांक 6 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 23/2006-सीमा-शुल्क द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क तथा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया है।

2. विचाराधीन उत्पाद

पूर्ववर्ती जांचों तथा वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद सोडियम फॉर्मेलिडहाइड सल्फोजाइलेट (एसएफएस) है। यह एक अकार्बनिक रसायन है जो हल्की विशेष गंध के साथ सफेद कतलों, चूर्ण, चावल व मटर के आकार के दानों के स्वरूप में पाया जाता है। एसएफएस का उत्पादन, जस्ते के चूर्ण, पानी तथा सल्फर डाइआक्साइड की रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा किया जाता है। उत्पाद के विभिन्न स्वरूपों में कोई वास्तविक अंतर नहीं होता है। विभिन्न स्वरूपों का उत्पादन ग्राहक के अंतिम अनुप्रयोग की अपेक्षा पर निर्भर और विभिन्न स्वरूपों का एक ही सामान्य प्रयोजन होता है। सोडियम फॉर्मेलिडहाइड सल्फोजाइलेट (एसएफएस) का उपयोग मुख्यतः टेक्सटाइल प्रिंटिंग में एक शक्तिशाली निस्सरण अभिकर्ता के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग सफेद निस्सरण

अधिकर्ता अथवा रंगीन निस्सरण अधिकर्ता के रूप में भी किया जा सकता है। रबड़ उद्योग में इसका उपयोग स्टाइरीन-बूटाडाइन रबड़ के उत्पादन में उत्प्रेरक अधिकर्ता के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य वस्तुओं, पॉलिमर्स, प्लेबजों तथा विविध उद्योगों में भी किया जाता है।

सोडियम फॉर्मेलिडहाइड सल्फोजाइलेट (एसएफएस) को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के उपशीर्ष सं. 28311020 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि यह सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

3. जांच की शुरुआत

अधिनियम तथा नियमों के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करना अपेक्षित होता है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 2006 के डब्ल्यूटी सं. 16893 द्वारा यह आदेश दिया है कि यह निर्धारित करने के लिए मौजूदा शुल्क को समाप्त करने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं, निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है। अतः प्राधिकारी पाटनरोधी नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता तथा इस बात का पता करने के लिए क्या इस शुल्क को समाप्त करने से पाटन एवं क्षति के जारी रखने अथवा उसके जारी रखने की संभावना है, की समीक्षा करने के लिए एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

4. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन. गण. है।

5. जांच की अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 (12 महीने) की है। तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा जांच की अवधि शामिल होगी। पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए जांच अवधि के अलावा भी आंकड़ों की जांच की जा सकती है।

6. प्रक्रिया

दिनांक 25 जनवरी, 2006 की अधिसूचना सं. 14/25/2004-डीजीएडी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम तथा दिनांक 6 मार्च, 2006 की सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 23/2006 द्वारा लगाए गए अंतिम शुल्क की समीक्षा का निर्णय लेने के पश्चात् प्राधिकारी यह बताने के लिए कि क्या लगाए गए शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है तथा सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का अधिज्ञान, आकलन तथा वसूली एवं क्षति निर्धारण हेतु) नियम, 1995 के अनुसार चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने पर पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं, एतद्वारा समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

7. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में उनके प्रतिनिधि कार्यालय के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :—

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग,
भारत सरकार
कमरा नं. 240,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा में जांच से संगत निवेदन कर सकता है।

8. समय-सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन (चालीस दिन) के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि ज्ञात निर्यातकों एवं आयातकों जिन्हें अलग से लिखा गया है, को यह सूचना उन्हें अलग से भेजे गए पत्र की तारीख से चालीस दिन के भीतर भेजनी होगी। यदि निर्धारित समय-सीमा

के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों को पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए अपनी प्रतिक्रिया 40 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए एक प्रश्नावली जारी की जा रही है।

सभी हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच के प्रारंभ होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने हित (हित की प्रवृत्ति सहित) के बारे में सूचित करने के लिए एतद्वारा सलाह दी जाती है। इस प्रकार सूचित करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों को पाटनरोधी उपाय जारी रखने की आवश्यकता अथवा अन्यथा के संबंध में पत्र जारी करने की तारीख से 40 दिनों के भीतर, घरेलू उत्पादकों की प्रतिक्रिया (प्रतिक्रियाओं) पर अपनी टिप्पणियां देने का अनुरोध किया जाएगा।

9. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना :

सभी हितबद्ध पक्षकार उपर्युक्त नियम के नियम 7(1) के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली गोपनीय सूचना के लिए नियम 7(2) के संदर्भ में एक गोपनीय और एक अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराएंगे। गोपनीय सूचना का अगोपनीय रूपांतर अथवा अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत हो जिससे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना की एक अर्थपूर्ण समझ प्राप्त हो सके। यदि सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसका कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। उपर्युक्त पैराग्राफ में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीय का अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रस्तुत करने वाला सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है अथवा सामान्य सारांश रूप में उसका प्रकटन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।

10. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण :

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय सारांश वाली उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

11. असहयोग :

यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

Initiation Notification

New Delhi, the 22nd June, 2010

(Sunset Review)

Sub : Initiation of Sunset Review Investigation of anti-dumping duty imposed against imports of Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) originating in or exported from China PR.

No. 15/16/2009-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) recommended imposition of provisional Anti Dumping Duty on imports of Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China P R vide notification No. 14/25/2004-DGAD dated 26th August, 2005. The Authority issued final findings vide notification No. 14/25/2004-DGAD dated 25th January, 2006. On the basis of the findings, the Central Govt. imposed provisional anti-dumping duty and definitive antidumping duty vide notification Nos. 95/2000-Customs, dated 11th November, 2005 and 23/2006-Customs dated 6th March 2006 respectively.

2. Product under consideration :

The product under consideration in the previous investigations and the present sunset review is Sodium Formaldehyde Sulfoxylate (SFS). It is an inorganic chemical, in the form of white chips, powder, price- pea sized granules with slight characteristic odour. SFS is produced by chemical reaction of zinc dust, water and sulphur dioxide. There is no material difference in the different forms of the product. Production of different forms depends on the requirement of end application of the customer and different forms serve the same general purpose. Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) is mainly used as powerful discharging agent in textile printing. It can also be used as white discharging agent or colour discharging agent. In the rubber industry it is used as an activating agent in the production of styrene-butadiene rubber. It also finds uses in food, polymers, pharmaceuticals and miscellaneous industries.

Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-headings No. 28311020. The Custom classification is, however, indicative only and not binding on the scope of investigations.

3. Initiation :

The Act and the Rules require the Authority to conduct review of anti dumping duty earlier imposed Hon'ble Delhi High Court has also held in WP No. 16893 of 2006 that sunset review is mandatory in order to determine whether cessation of the existing duty is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury. Therefore the Authority hereby initiates a sunset review investigation in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of Antidumping Rules to review the need for continued imposition of duties in force and to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. Country involved :

The country involved in this investigation is China PR.

5. Period of Investigation :

The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st April, 2009 to 31st March, 2010 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2006-07, 2007-08, 2008-09 & POI. The data beyond POI may also be examined to determine likelihood of dumping and injury.

6. Procedure :

Having decided to review the final findings issued *vide* Notification No. 14/25/2004-DGAD dated 25th January, 2006 and final duty imposed *vide* Customs Notification No. 23/2006 dated 6th March, 2006, the Authority hereby initiates investigations to review the need for continued imposition of duties in force and to examine whether cessation of Anti Dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury on imports of subject goods originating in or exported from China in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

7. Submission of Information :

The exporters in subject country, the government of subject country through its representative office in India, the importers and users in India known to be concerned with the product under consideration and the domestic industry, are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address :

Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Government of India
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. Time Limit :

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules

supra.

The domestic producers of the subject goods are being issued a questionnaire to respond within 40 days substantiating the need for continued imposition of the AD measures.

All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter within 40 days from the date of initiation of this investigation. All such interested parties, that intimate so, would be requested to offer their comments to the domestic producers' response(s) within 40 days from the date of issuance of the letter to them regarding the need to continue or otherwise the AD measures.

9. Submission of information on non-confidential basis

All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2), for the confidential information provided as per Rule 7(1) of the Rules supra. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing information, such information is not susceptible to summary; a statement of reasons thereof is required to be provided.

Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

10. Inspection of public file :

In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

11. Non-cooperation :

In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority